ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेज 4

सर्वश्रेठ गोपालक बने महेन्द्र सिंह धोनी

रविवारीय, 07 - 13 मार्च 2021 वर्ष- दो, अंक-31, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

बगिया वाले बाबा ने लगा डाले साढे तीन लाख पेड़

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के मीगनीं गांव के रहने वाले 61 साल के माताप्रसाद तिवारी बगिया वाले बाबा के नाम से लोकप्रिय हैं। 1989 में जब उनके गांव में सूखा पड़ा तो वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरा समय वृक्षारोपड़ को देने लगे। तब गांव वालों को उनका यह प्रयास पागलपन लगता था, इसलिए उनका नाम पागल बाबा पड़ गया। अब वही गांव वाले उन्हें बगिया वाले बाबा के नाम से बुलाते हैं। माताप्रसाद ने अपने गांव में 25,000 पेड़ लगाकर एक ऐसी बगिया तैयार की है, इस बगिया में उन्होंने आम, अमरूद, बेर, कटहल, शरीफा, नीम, पीपल , बरगद जैसे फलदार और छायादार पेड़ लगाकर गर्मी में भी सुकून देने वाला 5 हेक्टेयर का क्षेत्र विकसित कर दिया है।

सफल और उम्मीदों वाला रहा राज्यस्तरीय किसान मेला

वरीय संवाददाता

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 5 से 7 मार्च तक प्रादेशिक एवं राज्यस्तरीय किसान मेले का सफल आयोजन संपन्न हो गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यस्तरीय एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाता है. वर्ष 2020 में इसका आयोजन नहीं किया जा सका था। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया।

उन्होंने कहा कि किसान परिवार से जुड़े होने की वजह से किसानों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को समझती हूँ । सीमित कृषि योग्य भूमि में देश की भावी खाद्यान जरूरतों को कम भूमि, कम जल एवं कम श्रमिक आधारित अधिक उत्पादन एवं लाभ वाली तकनीकों से ही पूरा किया जाना संभव होगा। राज्य बहुतायत छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका एवं पोषण सुरक्षा के लिए समेकित कृषि प्रणाली को पहली प्राथमिकता देनी होगी. राज्य में कृषि विकास को गति देने के लिए किसानों को कृषि तकनीक के नये आयामों जैसे संरक्षित कृषि, ड्रीप इरीगेशन एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, बायोटेक्नोलॉजी, नेनो टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एग्रीकल्चर और सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की दिशा में किसानों के बीच अधिकाधिक जागरूकता एवं कौशल विकास कार्यक्रम को चलाये जाने की जरूरत हैं. कृषि वैज्ञानिकों को स्थानीय उपयुक्त लाभकारी नवाचार तकनीकी को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा. हरेक वर्ष तकनीकी नवीनता के साथ मेले का आयोजन आयोजन विश्विद्यालय की विशेषता एवं पहचान है. आधुनिक प्रौद्योगिकी, सेवाओं, उपादानों और उत्पादों के जीवंत प्रदर्शन का किसान मेला सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है. अधिकाधिक किसान इस अवसर का लाभ लें.

इस मौके पर पशुपालक कैलेंडर, आधुनिक सूकर पालन के आयाम व जीव रसायन प्रश्न बैंक पुस्तिका का विमोचन किया गया. साथ ही कृषि उद्यमिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दुमका की सपना कुमारी, मछली उत्पादन में गढ़वा के गौरव साव, सूकर पालन में नगड़ी के सौरव उराँव तथा पपीता की खेती में प. सिंहभूम के महेश पूर्ति तथा बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा को द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राम लखन सिंह ने मेले से किसानों को आत्मनिर्भरता के ज्ञान को सीखने और कौशल विकास का अवसर बताया. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कृषि विस्तारीकरण को बड़ा कदम की बात कही.

बीएयू में शिक्षकों,वैज्ञानिकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के खाली पदों को तुरंत भरे जाने की जरूरत

विशिष्ट अतिथि रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखण्ड में सरप्लस उत्पादित कृषि उत्पादों को उचित मूल्य मिलने के लिए देश के कोने-कोने तक के बाजार में किसानों के पहुँच को जरूरी बताया. झारखण्ड से जल्द ही सप्ताह में एक दिन देश के कोने - कोने तक किसान मेल ट्रेन की सुविधा उपलब्धता के बारे में बताया. इससे किसानों को कृषि उत्पाद बेचने में आसानी, मंडी टैक्स से निजात तथा किसानों के आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा.

मौके पर विशिष्ट अतिथि स्थानीय विधायक समरी लाल ने राज्य सरकार से कांके स्थित एशिया के सबसे बड़े बेकन फैक्ट्री को पुनः खोलने की मांग की. राज्य में आदिवासी के बीच सूकर पालन प्रचलित होने की वजह से इसे जरूरी बताया. साथ ही एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों,वैज्ञानिकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के खाली पदों को तुरंत भरे जाने की मांग की।

स्वागत भाषण में कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने तीन दिवसीय किसान मेला के थीम कृषि उद्यमों के विविधिकरण द्वारा ग्रामीण सम्पन्नता विषय पर प्रकाश डालते हुए मेले के महत्त्व पर प्रकाश डाला. मेले के ग्यारह सब थीम विषयों जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसलोत्पादन एवं समन्वित कृषि प्रणाली, फसल सुधार, फसल कीट एवं रोग प्रबंधन, द्वितीयक कृषि, कटाई उपरांत प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, फार्म यंत्रीकरण,उर्जा प्रबंधन, बीज एवं उपादान, ...शेष पेज 4 पर

कर्जविहीन किसान ही खुशहाली की पहचान : डॉ. रामेश्वर उरांव

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एवं विस्तार निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक एवं एग्रोटेक - 2021 किसान मेला का समापन रविवार को हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि

पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक एवं एग्रोटेक - 2021 किसान मेला का समापन

वित्त व योजना मंत्री डॉ रामेश्वर उराँव ने गरीब,किसान, मजदूर एवं भूमिहीन लोगों के हित में सरकार की प्राथमिकता की बात कही. किसान जन्म से लेकर मरण तक कर्ज में जीता है. कर्जविहीन किसान को प्रदेश की खुशहाली की पहचान बताया. कहा कि कोरोना के कारण किसानों की कर्ज माफ़ी में देरी हुई. राज्य की वित्त व्यवस्था में सुधार होते ही अगले वर्ष किसानों की एक लाख तक का कृषि सरकार माफ़ करेगी. उन्होंने कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने, किसानों को कम कृषि लागत से उचित मूल्य व अधिक मुनाफा से किसानों की आय बढ़ाने तथा किसानों के कल्याण में हर संभव मदद की बात कही.

डॉ. उराँव ने कहा कि देश में किसानों के हित में अनेकों रिसर्च हो रहे है. रिसर्च से मिले तकनीकों का आदिवासी किसानों को गाँवों तक लाभ दिलाने की कोशिश होनी चाहिए. कहा कि कृषि तकनीकी विकास की दिशा में विश्वविद्यालय का प्रयास सराहनीय रहा है. जिले के कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय में मानव बल की कमी से कार्य प्रभावित हो रहा है. विवि में मानव बल की कमी को जल्द दूर की जायेगी. मौके पर विशिष्ट अतिथि खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कोरोनाकाल में जान जोखिम में रखकर किसानों के खेती - खलहानी तथा देश की अर्थव्यवस्था बनाये रखने में योगदान की सराहना की. कहा कि उन्नत कृषि तकनीकी से ही किसान खुशहाल होंगे व खाद्यान्न संकट दूर की जा सकती है. किसान खेतों में उन्नत तकनीकी को अपना रहे है. किसानों के हित में सरकार की महत्त्वकांक्षी कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन में बीएयू की बड़ी भूमिका का होना जरूरी है। प्रगतिशील किसान शिव उराँव ने कृषि कर्ज माफ़ी पर वित्त मंत्री डॉ उराँव का आभार जताया। .....शेष पेज तीन पर

रांची आस पास के जंगलों में आग ही आग

डॉ. नितिश प्रियदर्शी

ये सारी तस्वीरें मैंने 6 मार्च शाम को ली है । रांची के पास जोन्हा फाल्स से लेके सीता फाल्स और अनगड़ा के जंगलों में कई जगह आग लगी हुई है। ऊँचे - ऊँचे पहाड़ों पे भी आग लगी हुई है। ये आग धीरे धीरे फ़ैल रही थी। वहां के लोग भी बोल रहे थे की पता नहीं कौन आग लगा गया है। वो भी गुस्से में थे। जंगल में और घाटी में चारो तरफ धुआं भरा हुआ था। पक्षी काफी परेशान हो रहे थे। सूखे हुए पत्तों में आग लगने से हरे भरे पेड़ों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जंगलों में आग लगने के कई वजह हैं लेकिन कारण कुछ भी हो पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के आग की त्रासदी को शायद हम भूल गए हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि महुआ चुनने वालों ने या पशु चराने वाले लोगों ने ये आग लगाई है। जो भी हो इससे वनों एवं पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है।

रांची पहाड़ी मंदिर के झाड़ियों में लगी आग

रांची : शनिवार को रात वक्त पहाड़ी मंदिर के पिछले हिस्से में झाड़ी में असमाजिक तत्वों ने आग लगा दी। गर्मी की वजह से आग तुरंत भड़क उठी। आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सुखदेवनगर थाना पुलिस को दी। पुलिस की सूचना पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के कोषाध्यक्ष अभिषेक आनंद ने कहा कि मंदिर परिसर में उगी झाड़ियों में देर शाम आग लग गयी. इससे अफरा-तफरी मच गयी. झाड़ियों में अचानक धुआं का गुबार उठने लगा और देखते-देखते आग काफी तेजी से फैल गयी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. दमकल की गाड़ियों की मदद से आग को बुझाने का का काम किया गया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। आग लगने के कारण पहाड़ी स्थित पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी मंदिर समिति ने कहा है कि आग लगने के जगह की साफ सफाई करवायी जायेगी।

सीसीएल सीएमडी ने किया रेस्क्यू टीम को सम्मानित

रांची संवाददाता : सीसीएल के एन के क्षेत्र में आज वीआईपी क्लब में 'कर्मवीर सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया। सभी सीसीएल के कर्मवीर को भूमिगत खदान के पूनः शुरूआत (Re opening of Churi Underground Mine) के लिए उन्हें प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि सीएमडी सीसीएल, पी एम प्रसाद तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में निदेशक तकनीकी (संचालन) वी के श्रीवास्तव, सीवीओ सुमित कुमार सिन्हा सहित सीएमडी के तकनीकी सचिव मोहन वी रजिमवाले, महाप्रबंधक उमेश सिंह सहित महाप्रबंधक (रेस्क्यू) राजीव कुमार सिन्हा पी रंगनाथेश्वर एवं अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों के रेस्क्यू टीम के कर्मवीरों को सम्मानित किया। सीएमडी ने रेस्क्यू टीम की प्रशंसा करते हुये कहा कि कंपनी कोयला उत्पादन के साथ-साथ सेफ्टी पर विशेष ध्यान रखता है और हमारे खान सुरक्षा कर्मी सदैव इस कार्य के लिए समर्पित हैं। समारोह को वी के श्रीवास्तव, सुमित कुमार सिन्हा ने भी संबोधित किया और कहा कि विगत वर्ष में सेफ्टी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कोल मिनिस्टर अवार्ड से सीसीएल को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का संचालन कमलेश कुमार सिंह ने किया तथा स्वागत भाषण महाप्रबंधक, एन के क्षेत्र संजय कुमार ने किया।

इस अवसर पर महाप्रबंधक के के सिन्हा, ए के ओझा, मनोज कुमार, दिलीप कुमार सिंह, आर आर शर्मा, के डी प्रसाद, भावेश कुमार राठौर, आर एस ग्रीन मनीष मोहन, रत्नेश कुमार, हरिशंकर सिंह, ललन सिंह, एसके चौधरी, रवींद्रनाथ सिंह, प्रेम कुमार, विनय सिंह, मानकी, मनोज रजक, शैलेश कुमार, डीपी सिंह, कृष्णा चौहान, अमर भूषण सिंह, सुनील कुमार सिंह, गोल्डेन यादव, ध्वजा राम धोबी व अन्य उपस्थित थे।

पशुओं से प्रेम का संदेश दे रही हैं वेटनरी छात्रा पल्लवी घोष

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष

संवाददाता

आज भी समाज के बड़े तबके में पशुओं के प्रति करूणा का अभाव है, जिसे बदलने की जरूरत है।

रांची :इंसान के करूणा एवं स्नेह के पशु-पक्षी भी हक़दार है, हमारे समाज के हर तबके तक यह संदेश देने से जुड़ी हैं कांके रोड निवासी पल्लवी घोष। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत रांची वेटनरी कॉलेज की छात्रा पल्लवी पशुओं की चिकित्सा, पोषण और देखभाल के साथ उनके अधिकारों के लिए भी आवाज बुलंद कर रही हैं।

बेजुबान जानवरों के प्रति आम लोगों का नजरिया बदले, इसके लिए वे नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाती हैं. पशुओं की देखभाल पर आधारित उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल पैलिडोस्कोप शुरू किया है, जो देखते ही देखते पशु प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो गया. पशुओं के रख-रखाव, टीकाकरण व पोषण पर आधारित उनके 30 से भी अधिक वीडियो को यूट्यूब चैनल पर काफी पसंद किया जा रहा है। डीपीएस रांची से बारहवीं शिक्षा लेने वाली छात्रा पल्लवी घोष डॉक्टर बनना चाहती थीं. मेडिकल में दाखिला नहीं मिली, तो उन्होंने मायूस होने के बजाय वेटनरी शिक्षा को चुना. वे कहती है कि उन्हें पशुओं से लगाव था, तो सोचा कि अगर इसकी पढाई की जाए तो बेहतर तरीके से उनके लिए काम किया जा सकता है. अभी वे कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं।

पल्लवी बताती हैं कि पढाई के दौरान यह महसूस हुआ कि इंटरनेट पर भी पशुओं पर आधारित पाठ्य सामग्री बहुत सीमित है. इसके बाद उन्होंने पशुओं में होने वाली बीमारियों, उनके टीकाकरण, उनकी त्वचा की देखभाल, खान-पान, पोषण और उनके बर्ताव पर आधारित वीडियो बनाना शुरू किया. यह इतना पसंद किया गया कि देश-विदेश से उनके यूट्यूब वीडियो को व्यूज मिलने लगे। हाल ही में पल्लवी, उनके साथी प्रभांशु कुमार और सुरभी कुमारी की टीम ने अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, लुधियाना की ओर से आयोजित राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजेता बनने का गौरव हासिल किया. इसमें देशभर से 28 वेटनरी कॉलेज के विद्यार्थियों की प्रतिभागिता थी.शनिवार को बीएयू में आयोजित किसान मेला में इन्हें कुलपति द्वारा सम्मानित किया गया. पल्लवी कहती हैं कि आज भी समाज के बड़े तबके में पशुओं के प्रति करूणा का आभाव है, जिसे बदलने की जरूरत है. बीएयू कुलपति डॉ ओएन सिंह ने इसे यूट्यूब चैनल की दुनिया में पशुपालन एवं पशुचिकित्सा क्षेत्र का एक नया आयाम बताया. डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद ने पल्लवी के इस प्रयास को पशुपालन एवं पशुचिकित्सा क्षेत्र में थ्योरी व प्रैक्टिकल ज्ञान के बीच की दूरी को कम करने वाला सराहनीय कदम कहा है।

The Palleidoscope

कैसे मिलेगा सबको आशियाना?

2022 तक कैसे पूरा होगा 'सबके लिए घर' का सपना, तीन साल में केवल 37.6 फीसदी मकान ही बने पाये हैं। पिछले तीन वर्षों (2017 से 2020) में केवल 29,85,212 घर ही बन पाए हैं जबकि 79,44,126 घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। पिछले तीन वर्षों (2017 से 2020) में केवल 29,85,212 घर ही बन पाए हैं जबकि 79,44,126 घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। जिसका मतलब है कि इस अवधि में केवल 37.6 फीसदी ही मकान बन पाए हैं। गौरतलब है कि शहरी इलाकों में सबके लिए अपना घर के सपने के साथ जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी की शुरुआत की गई थी। जिसका मकसद जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर मकान बना कर देना था।

इस योजना के तहत अब तक 109,88,765 घरों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है जबकि अब तक केवल 42,00,797 मकान ही बन पाए हैं। यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा राज्य सभा में दिए एक उत्तर में सामने आई है।सरकार को उम्मीद है कि 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा, पर विकास की इस रफ़्तार को देखते हुए यह कैसे पूरा होगा यह एक बड़ा सवाल है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली और चंडीगढ़ में ही जितने मकान स्वीकृत हुए थे उनका निर्माण पूरा हो चुका है। इनकों छोड़कर किसी ने भी स्वीकृत मकानों के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया है। वहीं यदि आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्माण की स्थिति सबसे ज्यादा सुस्त है, वहां अब तक स्वीकृत मकानों में से 50 फीसदी भी नहीं बन पाए हैं।मध्यप्रदेश में केवल 7.5 फीसदी मकान बने हैं। देश में सबसे ज्यादा आंध्रप्रदेश में 20.26 लाख मकान स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से केवल 17.6 फीसदी ही बन पाए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 17.67 लाख मकानों को स्वीकृति मिली थी उनमें से केवल 39.3 फीसदी बने हैं। महाराष्ट्र में स्वीकृत 12.86 लाख मकानों में से करीब 32 फीसदी ही पूरे हुए हैं। यानि अपने आशियाने का सपना पूरा होना बहुतों के लिये अभी दूर है।

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली और चंडीगढ़ में ही जितने मकान स्वीकृत हुए थे उनका निर्माण पूरा हो चुका है। इनकों छोड़कर किसी ने भी स्वीकृत मकानों के निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया है। वहीं यदि आंकड़ों पर गौर करें तो देश में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्माण की स्थिति सबसे ज्यादा सुस्त है, वहां अब तक स्वीकृत मकानों में से 50 फीसदी भी नहीं बन पाए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है, जहां केवल 6.5 फीसदी मकान ही बन पाए हैं। मध्यप्रदेश में 7.5 फीसदी, मणिपुर 9.8 फीसदी, मिजोरम में 11.9 फीसदी, हरियाणा में 12.5, नागालैंड में 13.4 फीसदी, जम्मू और कश्मीर में 17.1, आंध्रप्रदेश में 17.6 फीसदी और असम में 20 फीसदी मकान ही बने हैं।

भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाए स्वदेशी स्पेक्ट्रोग्राफ

इस स्पेक्ट्रोग्राफ को देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है इसकी कीमत विदेश से आयात किए जाने वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से करीब ढाई गुना कम है

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए स्पेक्ट्रोग्राफ को देवस्थल ऑप्टिकल टेलिस्कोप में लगाया गया है इस स्पेक्ट्रोग्राफ को देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसकी कीमत विदेश से आयात किए जाने वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से करीब ढाई गुना कम है इनकी मदद से बहुत दूर स्थित तारों और आकाशगंगाओं से निकलने वाले हलके प्रकाश और उसके स्रोत का पता लगाया जा सकता है। यह उपकरण लगभग एक फोटॉन प्रति सेकंड की फोटॉन दर के साथ प्रकाश के स्रोत का पता लगा सकते हैं। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सामने आई है। इससे पहले इन स्पेक्ट्रोग्राफ को विदेश से आयात किया जाता था, जिससे यह बहुत महंगे पड़ते थे पर अपने देश में ही विकसित इन स्पेक्ट्रोग्राफ की कीमत ढाई गुना कम है इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), नैनीताल में विकसित किया गया है। इसपर करीब 4 करोड़ रुपए का खर्च आया है

इसको एरीज- देवस्थल फैंट ऑब्जैक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा (एडीएफओएससी) नाम दिया गया है इसे 3.6-एम देवस्थल ऑप्टिकल टेलिस्कोप (डीओटी) पर सफलता पूर्वक स्थापित कर दिया गया है गौरतलब है कि यह टेलिस्कोप नैनीताल, उत्तराखंड के पास है, जो एशिया में सबसे बड़ा है। यह एक विशिष्ट उपकरण है, जो देश में उपलब्ध स्पेक्ट्रोग्राफ में सबसे बड़ा है यह बेहद मंद और धुंधले आकाशीय स्रोतों की निगरानी के लिए 3.6-एम देवस्थल ऑप्टिकल टेलिस्कोप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें विशेष कांच से बने कई लेंसों की एक जटिल संरचना है साथ ही इसमें आकाश से संबंधित चमकदार छवियों को प्राप्त करने के लिए 5 नैनोमीटर स्मूथनेस की पॉलिश की गई है। यही वजह है कि यह आकाशगंगाओं के आसपास मौजूद ब्लैक होल्स से लगे क्षेत्रों और ब्रह्माण्ड में होने वाले धमाकों और दूर आकाशगंगाओं में स्थित तारों से निकलने वाले मंद प्रकाश के स्रोत का पता लगाने में सक्षम है

नाजुक चमोली सिर्फ ऊंचे पहाड़ों से नहीं बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से भी घिरा है

विवेक मिश्रा

जल विद्युत परियोजनाओं से ऊर्जा को डबल करने के लिए अगले कुछ दशकों में हिमालय पर सरकार करीब 229 डैम बनाना चाहती है। यदि ऐसा हुआ तो हर 32 किलोमीटर पर एक डैम होगा। मुझे खबर मिली तो मैंने तत्काल जोशीमठ की एसडीएम को संपर्क किया, वह दौरे पर निकल गईं। मैंने हैलीपेड की व्यवस्था की और सुबह 10 बजे के बाद से ही हमने वायरलेस के जरिए आपदा नियंत्रण कक्ष से अधिकारियों से बातचीत और आदेशों की घोषणाएं शुरु कर दीं। 7 फरवरी, 2021 की सुबह हरिद्वार के आगे जोशीमठ तक आवाजाही बंद कर दी गई। आस-पास के जिलों में अधिकारियों से संपर्क बना रहा। शाम होने तक जब पानी का चढ़ना कम हुआ तब जोशीमठ तक आवाजाही के लिए अनुमति दी गई।

चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने यह बातें साझा की। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा यह नहीं कह सकते हैं। अब तक 72 मृत्यु की पुष्टि हो चकी है और 132 लोग लापता हैं। लेकिन यह आपदा क्यों घटित हुई यह जवाब उनके पास नहीं है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों की रायों को जानना होगा। चमोली की इस त्रासदी में सरकार और वैज्ञानिकों को पहले इस आपदा के घटित होने का सिरा नहीं मिल रहा था। स्थानीय ग्रामीण और जनसंगठन जल विद्युत परियोजनाएं और निर्माण गतिविधियों को इसकी वजह बता रहे हैं। हालांकि, कोई स्पष्ट और समग्र रिपोर्ट अब तक इस मामले पर नहीं मिल सकी है कि आखिर ग्लेशियर का यह टुकड़ा चट्टान के साथ टूटा कैसे और इतनी बड़ी मात्रा में पानी नीचे की तरफ कहां से आया। यह सवाल अब भी अनुत्तरित हैं।

वाडिया इंसटीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) ने एरियल सर्वे और कुछ हिस्सों की ग्राउंड रिपोर्ट के प्राथमिक निष्कर्षों में इसे रॉक एवालांच कहा। रॉक एवलांच यानी जिसमें ग्लेशियर और चट्टान दोनों हिस्से शामिल थे। वाडिया इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस ग्लेशियर युक्त विशाल मलबे का अनुमानित आकार 2.2 करोड़ घन मीटर था। वहीं, मलबे के कारण रौंथी नाले और ऋषिगंगा नदी के मिलन स्थल पर एक प्राकृतिक डैम बना, जिसने पानी जमा किया और बाद में वह टूट गया, जिससे निचले क्षेत्रों में जानमाल की बड़ी तबाही हुई।

इससे पहले कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगेरी में एनवॉयरमेंट साइंस प्रोग्राम के निदेशक व जियोलॉजिस्ट डैनियल शुगर पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेटेलाइट इमेजरी के अध्ययन के आधार पर ग्लेशियर युक्त चट्टानी भूस्खलन के घटित होने और कृत्रिम डैम बनने का अंदेशा जताया था। उन्होंने कहा कि ''सेटेलाइट इमेज में दिखाई देने वाला धूल-गुबार एक ठोस तरीके से यकीन पैदा करने वाला तर्क (मेरे दिमाग में) पैदा करता है कि एक बड़ा भूस्खलन हुआ है।'' उन्होंने अपने शुरुआती कयास में कहा था कि यह संभव है कि ऋषिगंगा या धौलीगंगा के पास लैंडस्लाइड अस्थायी तौर पर ब्लॉक हो गया हो, एक झील बन गई हो और बाद में फट गई हो। वहीं, 09 फरवरी, 2021 को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) के निदेशक कलाचंद सेन ने बातचीत में कहा कि उनके पांच वैज्ञानिकों के दल ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक उत्तराखंड में 7 फरवरी, 2021 को चमोली में हुई जानलेवा आपदा ग्लेशियर के साथ चट्टानी टुकड़े के भूस्खलन (रॉक-आइस एवलांच) और एक कृत्रिम अस्थायी डैम बनने के कारण हुई।

सेन ने कहा ''बेहद बड़े आकार वाले रौंथी ग्लेशियर के ठीक बगल एक हैंगिग ग्लेशियर था। वहीं, लटकते हुए इसी हिमनद के नीचे एक बड़ा चट्टानी टुकड़ा (रॉक मास) भी था, जो कुछ समय में कमजोर हो गया। यानी धीरे-धीरे वीक प्लेन बना और ग्रैविटी के कारण यह ग्लेशियर और रॉक मास कमजोर होकर नीचे गिरा। जब यह रॉक एवलांच हुआ तो मलबे को रौंथी नाले तक पहुंचने के लिए 40 डिग्री स्लोप मिला जिसने करीब 1.8 किलोमीटर ढाल वाले रास्ते इसे और गति दी। बाद में इस रॉक मास और ग्लेशियर टुकड़े के साथ आए मलबे के कारण नीचे रौंथी नाला जहां ऋषिगंगा से मिलता हैं वहां एक अस्थायी कृत्रिम डैम भी बन गया। मिट्टी, बर्फ, ग्लेशियर का टुकड़ा, रॉक मास ने मिलकर नाले के मुंह को बंद किया। इस कारण धीरे-धीरे वहां बड़ी मात्रा में पानी भी जमा हो गया और अचानक यह कृत्रिम मलबे का डैम टूट गया, जिससे ऋषिगंगा और धौलींगंगा में काफी तबाही हुई।

वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि निर्माण गतिविधियों का असर इस आपदा का कारण न बना हो यह पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। परियोजनाओं का हस्तक्षेप और लगातार होने वाले विरोध ने इस पहलू को ज्वलंत बना दिया है। रैणी गांव और प्रवासी मजदूरों ने यह स्पष्ट किया कि परियोजनाओं के चलते विभीषिका बढी। ऐसे में परियोजनाओं की जांच-परख को लेकर अब फिर से सवाल उठ रहे हैं। परियोजनाओं से होने वाले नुकसान के चलते भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। वहीं, 2019 में सरकार ने भी कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों पर कोई नई जल विद्युत परियोजना नहीं बनाई जाएगी। हालांकि फिर सरकार ने कहा कि 13 परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें 7 परियोजनाओं का काम 50 फीसदी से ज्यादा पूरा हो चुका था। वित्तीय नफा-नुकसान पर बिठाए जाने वाली परियोजनाओं पर त्रासदी की चेतावनी साफ-साफ लिखी है लेकिन सरकारें शायद इसे पढ़ना नहीं चाहतीं। यही वजह है कि सरकार ने हिमायल में अगले कुछ दशकों में जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को दोगुना करने के लिए 292 डैम बनाने की लक्ष्य रखा है।

यदि सरकार 28 या 32 नदी घाटियों में अपनी रपरियोजनाओं को मूर्त रूप देती है तो दुनिया में सबसे ज्यादा डैम घनत्व यहीं होगा, हर 32 किलोमीटर पर एक डैम स्थापित होगा। इनमें से कुछ की ऊंचाई और चौड़ाई दुनिया में सर्वाधिक होगी। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवॉयरमेंट एंड वाटर ने अपने हालिया अध्ययन में बताया है कि 1970 से लेकर अब तक उत्तराखंड में 4 गुना ज्यादा त्रासदी बढ़ी है। शायद इसके पीछे कहीं-न-कहीं अस्थिर हिमालय को और ज्यादा अस्थिर करने वाली परियोजनाएं ही हैं।

2021 के पहले दो महीने किसानों पर भारी, कहीं सूखा तो कहीं भारी बारिश

जनवरी-फरवरी माह में भारत में सामान्य से 32 फीसदी कम बारिश हुई, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहा।

मौसम और किसान का तो बैर सा हो गया है। कभी बारिश होती है तो इतनी होती है कि फसल खराब हो जाती है और जब बारिश की जरूरत होती है, उस समय बारिश नहीं होती। इस बार जनवरी-फरवरी में बारिश ही नहीं हुई। किसी तरह मोटर-पंप का इंतजाम किया और गेहूं और मकई को बचाया, वर्ना तो दोनों फसल बर्बाद हो जाती।" यह कहना है, बिहार के मधेपुरा जिले के ब्लॉक ग्वालपाड़ा के गांव झटिकिसा कलौसा निवासी चिंटू का। चिंटू ने अपने दस एकड़ के खेत में मकई और पांच एकड़ के खेतों में गेहूं लगाया है। वह कहते हैं कि जनवरी-फरवरी में बारिश नहीं हुई तो जमीन सख्त होने लगी। इससे खरपतवार, कीड़ें दिखाई देने लगे तो हम लोग सचेत हो गए और तुरत-फुरत मोटर पंप से पानी की सिंचाई शुरू की गई और हर पांच दिन के अंतराल में दवाई का स्प्रे करना पड़ा। वह बताते हैं कि इस बार फसल बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी।

वहीं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में फरवरी में अचानक आई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद क्षेत्र के किसान अमित पारांडकर ने बताया कि 18-19 फरवरी की रात को इतनी तेज बारिश हुई कि हमारी सारी फसल तबाह हो गई। उन्होंने चना लगाया था, जिसे काफी नुकसान पहुंचा। उन्हें कुल 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। तब प्रशासन ने पंचनामा भी भरा था और कहा था कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। वह बताते हैं कि उनके इलाके में अंगूर की खेती बड़ी मात्रा में होती है। बारिश और ओलों की वजह से अंगूर के फाउंडेशन तक खत्म हो गए। अंगूर किसानों को दस लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है।

महाराष्ट्र के ही किसान जाकिर बताते हैं कि बीती सर्दी ही किसानों के लिए भारी रही। 2020 की दीवाली के बाद जब सर्दी का सीजन शुरू होता है तो उन्होंने अपने खेतों में हर साल की मौसम्बी फल के पेड़ों की पानी दिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक इस सीजन में ठंड पड़ी ही नहीं। इससे मौसम्बी सही से नहीं हुई। बाकी कसर, एक दिन ओलों के साथ-साथ हुई तेज बारिश ने पूरी कर दी। ज्यादातर कच्ची मौसम्बी गिर गई। यही हाल उनके गांवों के गेहूं किसानों का हुआ। गेहूं के लिए भी सर्दी जरूरी है, लेकिन इस सीजन में ठंड नहीं हुई तो गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ। उनका अनुमान है कि इस सीजन में गेहूं के उत्पादन लगभग आधा रह जाएगा। दरअसल, जनवरी और फरवरी का महीना मौसम के हिसाब से काफी खराब रहे। इन दो महीनों में दक्षिणी भारत को छोड़ कर शेष भारत में सामान्य से काफी कम बारिश हुई, जिसके चलते न केवल अधिकतम तापमान बढ़ गया, बल्कि रबी सीजन की फसल को लेकर भी किसानों की चिंता बढ़ गई है।

2 मार्च को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी व फरवरी में बारिश का दीर्घकालिक अवधि औसत (एलपीए) 40.8 मिलीमीटर रहता है, लेकिन 2021 के जनवरी-फरवरी महीने में देश में 27.8 मिलीमीटर बारिश हुई। जो औसत से लगभग 32 फीसदी कम रही। लेकिन अगर अकेले फरवरी माह की बात की जाए तो फरवरी में देश में 68 फीसदी बारिश कम हुई।एक ओर पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी कम बारिश हुई, वहीं दक्षिण प्रायद्वीप के राज्यों में औसत से काफी अधिक बारिश हुई।

मौसम विभाग के मुताबिक, 1901 के बाद 2021 में सर्दी के मौसम (जनवरी-फरवरी) में चौथी बार सबसे अधिक बारिश हुई। यहां इस साल 56.1 एमएम बारिश हुई, जबकि इससे पहले 1901 में 61 एमएम, 1986 में 59.9 एमएम, 1984 में 59.2 एमएम बारिश हुई थी। वहीं पूर्वी व पूर्वोत्तर राज्यों में 78 फीसदी कम बारिश हुई। इस क्षेत्र में दीर्घकालिक अवधि के औसत (एलपीए) 52.1 एमएम है, जबकि इस साल जनवरी-फरवरी में केवल 11.5 फीसदी बारिश हुई। इसी तरह उत्तर पूर्व क्षेत्र में एलपीए से 51 फीसदी और मध्य भारत में 42 फीसदी कम बारिश हुई। मौसम विभाग के ये आंकड़े बताते हैं कि रबी सीजन के दो महत्वपूर्ण महीनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में काफी कम बारिश हुई। वहीं इन इलाकों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहा।

मौसम विभाग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी-फरवरी के दो माह का औसत अधिकतम तापमान 27.47 सेल्सियस रहा, जबकि सामान्य अधिकतम तापमान 26.70 सेल्सियस रहता है। इसी तरह इन दो महीनों में औसत न्यूनतम तापमान भी अधिक रहा। यहां यह उल्लेखनीय है कि सामान्य तापमान या दीर्घकालिक अवधि तापमान (एलपीए) से आशय है कि 1981 से 2010 के औसत तापमान से है। इन सालों के औसत को मौसम विभाग सामान्य तापमान मानता है।

अगर फरवरी माह की बात की जाए तो इस माह में गर्मी अधिक रिकॉर्ड की गई और सामान्य तापमान के मुकाबले फरवरी 2021 में अधिकतम तापमान में अधिक वृद्धि हुई। खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। फरवरी माह में यहां का सामान्य तापमान 21.46 एमएम रहता है, लेकिन फरवरी 2021 में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतम तापमान 24.40 एमएम रहा, जो 2.94 एमएम अधिक रहा। बारिश न होने और तापमान में वृद्धि के साथ-साथ तेज हवाएं चलने से किसानों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं और जौ के लिए यह मौसम ठीक नहीं रहा। मौसम को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से लगभग हर दिन सलाह जारी की जाती है। फरवरी माह के दौरान आईसीएआर की ओर से किसानों को बार-बार सलाह दी गई कि वे गेहूं और जौ में लगातार सिंचाई करें और खरपतरवार नाशक का भी प्रयोग करें।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020: बेंगलुरु और शिमला एक नंबर, श्रीनगर व मुजफ्फरपुर फिसड्डी

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों में जीवन की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग जारी की। 202010 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला पहले स्थान पर रहा। सीएसई 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला पहले स्थान पर रहा।

एक ऑनलाइन आयोजन में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (एमपीआई) 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की गई। इसकी दो श्रेणियां थी। पहली श्रेणी दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की थी, जबकि दूसरी में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया था।10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में उभरा, इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई का स्थान रहा। 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला ईज ऑफ लिविंग में सर्वोच्च स्थान पर रहा, इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे, और तिरुचिरापल्ली रहे। इसी प्रकार एमपीआई 2020 के तहत मूल्यांकन ढांचे में जनसंख्या के आधार पर नगरपालिकाओं को दस लाख से अधिक जनसंख्या वाली और 10 लाख से कम आबादी वाले नगरपालिकाओं में श्रेणीबद्ध किया गया है। इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगरपालिका के रूप में उभरा है।

गांव से महानगरों के खातों में पहुंचे पैसे

लॉकडाउन के कारण अप्रैल से जून तक के महीने में जबरदस्त रिवर्स रेमिटेंस हुआ। खासतौर से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के गांव व कस्बों से महानगरों में प्रवासी श्रमिकों के खातों में पैसे भेजे गए। इसे रिवर्स रेमिटेंस कहा जाता है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष के छह महीनों में काउंटर ट्रांजेक्शन में करीब 49 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है और ट्रांजेक्शन की वैल्यू भी 40 फीसदी कम रही है। इंडियन पोस्ट पेयमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक ईश्वरन वेंकटश्वरन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मार्च से अप्रैल के बीच ट्राजेक्शन की वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में कमी आई और रिवर्स रेमिटेंस का भी ग्राफी काफी बढ़ा लेकिन सितंबर तक स्थिति में सुधार आना शुरु हो गया। यह रुझान बेहद दिलचस्प है कि लॉकडाउन के दौरान रिसीवर यानी गांव-कस्बे ओर्जिनेटर बन गए।

कैसे हुआ हिमालय के विशाल पर्वतों का निर्माण वैज्ञानिकों ने पता लगाया

एजेंसियां

अध्ययनकर्ताओं ने आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए हिमालय पर्वतों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में पता लगाया है।

पहाड़ कैसे और कब विकसित होते हैं? पर्वतों का निर्माण करोड़ों साल के अंतराल में बहुत धीरे-धीरे होता है। एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे से धीरे-धीरे तब तक धक्का देती है, जब तक कि एक पर्वत श्रृंखला विकसित नहीं हो जाती है। बेशक, यह सब बहुत सरल लगता है, पर इतना आसान भी नहीं है। उदाहरण के लिए, कटाव और भूकंप जैसी प्रक्रियाएं पहाड़ों के बढ़ने के तरीके को प्रभावित करती हैं।हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंपों का अनुभव होता है, जो हिमालय और इसके निकट रहने वाली घनी आबादी दोनों के लिए खतरनाक है। अभी तक इन क्षेत्रों में कई भूकंप आ चुके हैं, जिनमें 2015 में नेपाल में आया 7.8 तीव्रता वाल गोरखा भूकंप, 2005 में कश्मीर आया 7.6 तीव्रता, 1950 में असम में 8.5- 8.7 तीव्रता, 1934 में बिहार-नेपाल में आया 8.4 तीव्रता, 1905 में कांगड़ा में आया 7.8 तीव्रता, 1897 असम-शिलांग पठार 8.2-8.3 तीव्रता का भूकंप शामिल हैं। हालांकि, बड़े हिमालयी भूकंपों में लंबे समय तक फिर से आने का समय अंतराल सैकड़ों सालों का होता हैं, सीमित यंत्रों से लिए गए रिकॉर्ड हमारी वैज्ञानिक समझ में बड़ी कमी छोड़ देता है, जिससे इस बात का पता लगाना कठिन हो जाता है कि भूकंप के खतरों से यह किस तरह लंबे समय तक जुड़ा रहता है और इससे कैसे निपटा जाएं।हिमालय के 200 से अधिक अध्ययनों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, कैलिफोर्निया इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) के पोस्टडॉक्टोरल फेलो लुका दाल जिलियो के नेतृत्व में एक टीम ने पर्वतों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में पता लगाया है। दाल जिलियो और उनके सहयोगियों ने भूकंप के दौरान पहाड़ों के हिलने के सेकंड से लेकर लाखों वर्षों तक चलने वाली लंबी अवधि की टेक्टॉनिक प्रक्रियाओं के बारे में पता लगाया है। यह अध्ययन नेचर रिव्यूज़ अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

दाल जिलियो ने कहा कि जब हम पहाड़ों की अवधारणा के बारे में सोचते हैं, तो हमें वास्तव में लगातार बदलने वाली चीजों के बारे में सोचने की ज़रूरत होती है और वे बदलाव अलग-अलग समय में अलग-अलग पैमानों के आधार पर होते हैं। दाल जिलियो कहते है कि शोधकर्ताओं ने पाया कि घटनाओं के माध्यम से हिमालय में पहाड़ बनने के चक्र बढ़ते है, जिससे उनकी सीमा बढ़ती और घटती रहती है। इससे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ सांस ले रहे हों। हालांकि, लाखों वर्षों में बढ़ती घटनाएं भूकंप के दौरान तेजी से कम होने वाली घटनाओं की तुलना में बड़ी होती हैं। लंबे समय तक चलने वाली यह प्रक्रिया हिमालयी रेंज के विकास की ओर ले जाती है।

शोधकर्ताओं ने भूगर्भीय और भूभौतिकीय आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें 2015 में नेपाल में आया विनाशकारी गोरखा भूकंप और उसके पीछे के कारणों की ओर इशारा करता है। उदाहरण के लिए, उपग्रहों से रडार छवियों का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने शुरुआत में पाया कि 7.8 तीव्रता के भूकंप आने के दौरान माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में लगभग एक मीटर तक की कमी आई। लेकिन उस घटना के महीनों बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि पहाड़ ने कम हुई ऊंचाई का लगभग 60 प्रतिशत पुनः प्राप्त कर लिया था। दाल जिलियो और उनके सहयोगियों ने हिमालय से पिछले कई दशकों के प्रेक्षणों पर ध्यान दिया, जैसे कि विभिन्न स्थानों पर पपड़ी की मोटाई और मुख्य हिमालयन फॉल्ट की ज्यामिति के बारे में जांच की जिसमें पहाड़ों के आधार पर लगभग 2,000 किलोमीटर लंबा दोष पाया गया।

दाल जिलियो ने हिमालय में आने वाले भूकंपों का अध्ययन करने के लिए मॉडल का भी उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मॉडल हमें यह समझने में मदद करता है कि पहाड़ आंशिक रूप से क्यों टूटा और भविष्य के लिए संभावित परिदृश्य क्या हैं। हिमालय कैसे विकसित होता है और समय के साथ कैसे बदलता है और भूकंप चक्र कैसे प्रभावित होता है, इसकी समझ विकसित करना विशेष रूप से मुख्य हिमालयन फॉल्ट की गतिविधि और बड़े भूकंपों के उत्पन होने के इतिहास को दिखाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए कटेंगे 1700 से ज्यादा पेड़

पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेड़ों को काटने की बजाय उन्हें हटा कर दूसरी जगह पर लगाया जाए

एजेंसियां : राष्ट्रीय राजमार्ग 59 के 40 किलोमीटर के विस्तार के लिए ओडिशा के गंजाम जिले में विभिन्न प्रजातियों के 1,720 पूर्ण विकसित और पुराने पेड़ों को काटा जाएगा। 126 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य बेरहमपुर शहर के पास रतनपुर और अस्का के पास मुंडमारई के बीच सड़क को 7 मीटर से 12 मीटर तक चौड़ा करना है।

ओडिशा राज्य वन विकास निगम ने रतनपुर में पहले ही कई पुराने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उड़ीसा में पौधारोपण के प्रचार व प्रसार में जुड़े स्वयंसेवी संगठन आर्यभट्ट फाउंडेशन के संस्थापक सुधीर राउत ने कहा कि सुपर साइक्लोन फैलिन ने 2013 में सड़क किनारे लगे कई बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया था। इसके बाद पेड़ों को दोबारा से लगाया गया, लेकिन अब सड़क को चौड़ा करने के लिए सभी सड़क किनारे के पेड़ों को काट दिया जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि पेड़ों को काटने की बजाय उचित मशीनरी का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जैसा कि देश के विभिन्न हिस्सों में किया गया था। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र की हरियाली और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखेगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में अधिकारियों से बात भी की है और प्रभागीय वनाधिकारी से संपर्क किया है, ताकि वह हस्तक्षेप करके इन पेड़ों को कटने से बचाएं। वहीं, जिला वन अधिकारी (डीएफओ) ने कहा कि जिन राज्यों में पेड़ों को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया गया है, वहां के परिणाम उत्साहजनक नहीं है। पेड़ों के जीवित रहने की संभावना काफी कम है। बावजूद इसके हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से इस काम को करने की संभावना तलाशी जा सके। ताकि मध्य उम्र के पेड़ों को कटने से बचाया जा सके।

खुंटी डीसी के सद्प्रयास से लापुंग साईं मंदिर के समीप लतरातु डैम में जलविहार तथा विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स होंगे प्रारंभ

लतरातु डैम में अब ले सकेंगे वाटर स्पोर्ट्स एवं नौकाविहार का आनंद

डैम में नौकाविहार करते खुंटी डीसी

ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षणार्थ गोवा रवाना करते डीसी एवं बीडीओ देवेश द्वीवेदी व अन्य

डैम में बोट के लिये एक प्लेटफार्म भी बन कर है तैयार

देवाशीष राय

लापुंग के साईं मंदिर से कुछ ही किमी आगे डुमरगझी गांव में लतरातु डैम है। यह कर्रा प्रखंड में आता है। लतरातु डैम को जमुनिया डैम भी कहते हैं। यूं तो साईं मंदिर और घघारी धाम घुमने आने वाले इस विशाल डैम को भी देखने आते हैं, पर अब खुंटी डीसी के प्रयास से इस डैम में नौका विहार एवं वाटर स्पोर्ट्स की भी शुरूआत की जा रही है।

लतरातु डैम तीन ओर से जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा हुआ है एक ओर बांध है जिस पर सड़क बनी हुयी है और इसी सड़क पर लोग आकर अब तक बांध को निहारते रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स और नौकाविहार के लिये बोट चालन एवं नावों को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये दर्जन भर से ज्यादा युवकों को डीसी ने गोवा भेजा है। यह युवक इसी गांव के हैं जो प्रशिक्षण के बाद यहां नौकाचालन से लेकर वाटर स्पोर्ट्स का काम देखेंगे। यह सब प्रारंभ होने पर पर्यटक सपरिवार भाड़े पर बोट लेकर नौकाविहार कर सकते हैं। डैम के आस पास के रहने वाले ग्रामीण भी इस प्रयास से बहुत खुश हैं। इस कार्य में डीडीसी अरूण कुमार सिंह तथा परियोजना निदेशक संजय भगत का सराहनीय योगदान रहा है।

पहले कभी नक्सल प्रभावित यह क्षेत्र अब पर्यटन और मत्स्यपालन की ओर अग्रसर है। यहां पास ही स्थित लापुंग के साईं मंदिर और रमणिक जंगल एवं घघारी झरने स्थित शिव मंदिर घूमने के लिये पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में लतरातु डैम में नौका विहार एवं वाटर स्पोर्ट्स के प्रारंभ होने से लोगों को सपरिवार घूमने का एक और मौका मिलेगा। यहां तक रांची से अच्छी सड़के बन गयी हैं। इन सुविधाओं के कारण आउटिंग करने वालों का यह पसंदीदा स्थान बन गया है।

झारखंड में अपार प्राकृतिक खुबसूरती है। लेकिन अब तक इसकी मार्केटिंग नहीं की गयी। यहां के पहाड़ों, जंगलों, झरनों, झीलों को अगर इकोफ्रेंडली तरीके से पर्यटन से जोड़ा जाये तो राज्य में रोजगार की भरमार हो जायेगी। यहां से पलायन रूक जायेगा और युवा अपने गांव में ही आजीविका पा सकेंगे। इसी प्रयास में हमने इस खुबसूरत जमुनिया डैम में वाटर स्पोर्ट्स एवं नौकाविहार शुरू करने की कोशिश की है।

शशि रंजन
डीसी, खुंटी

जल्द ही यहां रेस्टहाउस, रेस्टोरेंट तथा अन्य सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जायेगा। शौचालय निर्माण अब पूर्ण होने को है, सोलर पंप सिस्टम से यहां जल की उपलब्धता प्राप्त हो गयी है। जल्द ही यह इलाका मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी सफलता हासिल करेगा।

देवेश द्विवेदी (बीडीओ, कर्रा)

कोविड वैक्सीनेशन ड्राईव का दूसरा चरण सीसीएल में प्रारंभ

संवाददाता

सीएमडीसीसएल, पी.एम. प्रसाद ने बुजुर्गों एवं भारत सरकार द्वारा सूचित बीमारियों से ग्रसित 45+ आयु वर्ग के नागरिकों हेतु कोविड वैक्सीनेशन ड्राईव का शुभारंभ केंद्रीय अस्पताल, गांधीनगर में किया। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना)भोला सिंह, निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल, सीवीओ एस.के. सिन्हा सहित सीएमएस सीसीएल डॉ डी.के.एल. चौहान, डॉ रत्नेश जैन, डॉ अनजना झा, डॉ आर.के. सिंहएवं अन्य उपस्थित थे।

पी.एम. प्रसाद ने कहा कि यह हमारे देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का यह उल्लेखनीय योगदान है, जिन्होंने इतने कम समय में उत्कृष्ट कार्य करते हुए कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हमें मजबूती प्रदान की है। उन्होंने अपील की कि भारत सरकार द्वारा घोषित किये गए योग्यता मानदंडों में आने वाले सभी नागरिक वैक्सीन अवश्य लगवाए। सीसीएल ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब हम अपने अस्पतालों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत के साथ यह प्रयास को सतत जारी रखेंगे। निदेशकगणों ने देश को कोविड19 मुक्त करने की दिशा में की जा रही इस महत्वपूर्ण पहल हेतु सीसीएल की चिकित्सा टीम को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

सीसीएल ने ओबीएस का चेक सौंपा

रांची : सी.सी.एल. ऑफिसर्स बेनिवोलेन्ट सोसाईटी (ओ.बी.एस.) की ओर से 03 मार्च को सीसीएल मुख्यालय,दरभंगा हाउस, रांची में सीसीएल के निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव ने श्रीमती रेखा देवी, पति स्व. के.बी. पाण्डेय एवं श्रीमती गौरी वर्मन, पति स्व. पी.के. वर्मन को सीसीएल ओबीएस का रू. 4,50,000/- (रू. चार लाख पचास हजार) के अलग -अलग चेक प्रदान किये। रेखा देवी के पति स्व. के.बी. पाण्डेय अशोका प्राजेक्ट, पिपरवार क्षेत्र में पूर्व सबॉर्डिनेट इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे जिनका निधन विगत 17 दिसम्बर, 2020 को हो गया था। श्रीमती गौरी वर्मन के पति स्व. पी.के. वर्मन के.डी.एच. प्रोजेक्ट, एन.के. क्षेत्र में वरीय प्रबंधक (खनन)के रूप में कार्यरत थे जिनका निधन 31 दिसम्बर, 2020 को हुआ था। चेक प्रदान करने के दौरान निदेशक तकनीकी (संचालन) के तकनीकी सचिव के.एस. गैवाल, सीसीएल ओबीएस के महासचिव राज कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष संजीव प्रसाद, विनय कुमार शंकर, सुरेन्द्र प्रताप सिंह सहित उनके परिवार के सदस्यगण के साथ संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

रांची रेल मंडल पर अंतर रेलवे सेफ्टी ऑडिट

संवाददाता : रांची रेल मंडल पर अंतर रेलवे सेफ्टी ऑडिट के दूसरे दिन पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी शिव कुमार प्रसाद एवं उनकी टीम द्वारा हटिया स्थित रनिंग रूम तथा एकीकृत क्रू एवं गार्ड लॉबी का विस्तृत निरीक्षण किया गया। रनिंग रूम में क्रू तथा गार्ड के लिए उपलब्ध सुविधाएं जैसे रहने के लिए वातानुकूलित कमरा, व्यायाम के लिए मल्टी जिम, योग कक्ष, शाकाहारी एवं मांसाहारी रसोई कक्ष, रीडिंग रूम तथा शौचालय एवं स्नानघर की व्यवस्था का निरीक्षण किया, साथ ही रनिंग रूम के सभी रजिस्टर एवं शिकायत पुस्तिका का भी निरीक्षण किया । इसके पश्चात टीम द्वारा हटिया रेलवे स्टेशन स्थित एकीकृत क्रू एवं गार्ड लॉबी का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान कार्यरत कर्मचारियों से भी संरक्षा संबंधी एवं अन्य जानकारियां ली। रनिंग रूम तथा एकीकृत क्रू एवं गार्ड लॉबी के निरीक्षण के पश्चात उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की तथा जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार करने एवं इसे और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

इस दौरान रांची रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक एम एम पंडित, मुख्य अभियंता अमरेश कुमार, रोलिंग स्टॉक अभियंता अतुल प्रियदर्शी, मुख्य सिग्नल अभियंता एम के श्रीवास्तव, मुख्य विद्युत अभियंता वित्तरण आर पी भारती, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी (विद्युत) पी के सक्सेना एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी के सचीव आर के श्रीवास्तव तथा रांची रेल मंडल से वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (ट्रेक्शन)ए आर दास, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य) कुलदीप कुमार, मंडल विद्युत अभियंता दीपांजल सरकार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

रांची :पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगे।

ट्रेन संख्या 05027 हटिया - गोरखपुर स्पेशल ट्रेन दिनांक 14-03-2021 से दिनांक 18-03-2021 तक हटिया से चलने वाली अपने निर्धारित मार्ग बरौनी - समस्तीपुर - मुज़फ़्फ़रपुर - हाजीपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बरौनी - शाहपुर पटोरी - हाजीपुर होकर गोरखपुर जाएगी

ट्रेन संख्या 05028 गोरखपुर - हटिया स्पेशल ट्रेन दिनांक 15-03-2021 से दिनांक 19-03-2021 तक गोरखपुर से चलने वाली अपने निर्धारित मार्ग हाजीपुर - मुज़फ़्फ़रपुर - समस्तीपुर - बरौनी के स्थान पर हाजीपुर - शाहपुर पटोरी - बरौनी होकर हटिया आएगी ।

डुमरगढ़ी के जमुनिया डैम में मत्स्य पालन से जुड़ी महिलायें

संवाददाता

रांची : हाल के कुछ वर्षों में झारखंड ने मत्स्यपालन में बहुत अच्छी प्रगति की है। इसमें खुंटी जिले की प्रगति भी बहुत ही उल्लेखनीय है। राज्य में विशाल जलाशयों की भरमार है। कुछ वर्षों में इन जलाशयों में व्यावसायिक रूप से मछली पालन का कार्य प्रारंभ हुआ और अब इसका बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त हो रहा है। राज्य मत्स्य पालन में आत्म निर्भर हो गया है।

डुमरगढी स्थित जमुनिया डैम में जो खुंटी जिले के कर्रा प्रखंड में है वहां झारखंड स्टेट लाइवलीहूड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसपीएलएस) द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण देकर मत्स्य पालन से जोड़ा गया है। महिलायें उत्साह और समर्पण से इस कार्य में जुटी हुई हैं। डैम के एक हिस्से को जाल से घेर कर उसमें तीन प्रकार के कार्प मछलियों के बीज डाले गये हैं। जिनमें रोहू, कतला और मृगल हैं। एक साल में दो बार इन मछलियों को निकाल कर बाजार में उपलब्ध कराया जायेगा। इस गांव में इतना विशाल जलाशय उपलब्ध है इस कारण से महिलाओं को सिर्फ अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जो जेएसपीएलएस के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। जल्द ही यहां से मत्स्य उत्पादन शुरू हो जायेगा जो यहां के ग्रामीण महिलाओं को एक अच्छा रोजगार उपलब्ध करायेगा।

हम पूरे समर्पण के साथ इसे सफल बनायेंगे: श्याम सुंदर

मत्स्यपालन के इस परियोजना के जिला परिषद् के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर का कहना है कि हम इस क्षेत्र में महिलाओं के मत्स्यपालन में सफलता को लेकर समर्पित हैं और उम्मीद है कि जल्द ही यहां से अच्छी तादाद में मत्स्य उत्पादन प्रारंभ भी हो जायेगा। हमें इस इलाके में सफलता की अच्छी उम्मीद है।

वेटरीनरी कॉलेज के तीन छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली बड़ी सफलता

पल्लबी घोष

सुरभि कुमारी

प्रभांशु कुमार

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके अधीन संचालित रांची वेटरनरी कॉलेज के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है।

इस कॉलेज के इस वर्ष के बीवीएससी कोर्स के अंतिम सेमेस्टर तीन छात्रों के दल ने गुरु अंगददेव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, लुधियाना, पंजाब द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है. आईडीपी-नाहेप द्वारा प्रायोजित इस पांच दिवसीय राष्ट्रीय ई-सम्मेलन "वेट्स विज़न" को विश्वविद्यालय में एक मार्च से 5 मार्च तक आयोजित किया गया था. देश भर के 28 पशु चिकित्सा कॉलेजों के सैकड़ो छात्रों ने वर्चुअल माध्यम से तकनीकी प्रश्नोत्तरी से लेकर पोस्टर प्रस्तुतियों तक के कार्यक्रमों में भाग लिया. प्रतियोगिता में रांची वेटरनरी कॉलेज की छात्रा पल्लबी घोष व सुरभि कुमारी तथा छात्र प्रभांशु कुमार ने क्विज़ प्रतियोगिता के "स्मार्ट माइंड वेट्स" समूह में भाग लिया. जिसमें तीनों छात्रों ने पहली बार 3 मार्च को प्रतियोगिता का प्रारंभिक दौर क्वालीफाई किया. 4 मार्च को सेमीफ़ाइनल से फाइनल में पहुँचे.5 मार्च को देर शाम आयोजित फिनाले के तीनों छात्रों को विजेता घोषित किया गया. छात्रों को मिली सफलता से कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों में खुशी देखी गई. विवि कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह तथा कॉलेज के डीन डॉ. सुशील प्रसाद सहित प्राध्यापक डॉ मधुरेंद्र कुमार गुप्ता, डॉ.जगरनाथ उराँव, डॉ. आलोक कुमार पांडे, अन्य शिक्षकों तथा पीजी एवं पीएचडी छात्रों ने इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

...पेज एक का शेष

कर्जविहीन किसान ही खुशहाली की पहचान

शिव उराँव ने कहा कि कृषि विवि के गाँवो में कार्यक्रमों से अच्छे परिणाम दीखने लगा है. किसान स्वालंबन व आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे है. किसानों के हित में प्रदेश के सभी प्रखंडो में कृषि उत्पाद के लिए कोल्ड स्टोरेज को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है. अध्यक्षीय भाषण में कुलपति डॉ ओएन सिंह ने बताया कि मेले में छोटे, सीमांत व भूमिहीन किसानों को कृषि विविधीकरण से संपन्नता आधारित तकनीकी को प्रदर्शित किया गया. किसानों के बेहतरी के लिए लाभकारी कृषि तकनीकी विकास की दिशा में कृषि वैज्ञानिक शोध एवं प्रसार कार्यो को बढ़ावा देने में अथक प्रयास कर रहे है.

समारोह में दस सदस्यीय किसानों के दल ने कृषि कर्ज माफ़ी पर आभार जताते हुए वित्त मंत्री डॉ उराँव को पुष्प गुच्छ एवं माला पहनाकर आभार जताया. इस अवसर पर वित्त मंत्री व विधायक के द्वारा कृषि कार्यो में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसानों में शंकर सोरेन, शंकर महली, जगदीश महतो, कृष्ण कुमार राय, नरेश महतो, धनेश्वर महतो, मुन्नी देवी, सुधाकर मंदेवाल एवं अनिसूर रहमान तथा मास के विजय भरत को सम्मानित किया. कार्यक्रम का संचालन शशि सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ जगरनाथ उराव ने दी. मेला में देर शाम आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह में कुलपति डॉ ओएन सिंह ने पशु -पक्षी प्रदर्शनी में उत्कृष्टता के लिए कुल 108 प्रतिभागियों को पुरूस्कृत किया. साथ ही उद्यान प्रदर्शनी में उत्कृष्टता के लिए कुल 190 प्रतिभागियों को प्रथम एवं द्वितीय पुरूस्कार प्रदान किया.

महिलाओं का बिरसा बेबीकॉर्न में रूझान

मेले में कृषक महिलाओं में बीएयू द्वारा विकसित मक्का की किस्म बिरसा बेबीकॉर्न -1 व कम्पोजिट किस्म बिरसा मक्का 3 के प्रति काफी रुचि देखी गई. इन किस्मों का विकास महिला वैज्ञानिक पौध प्रजनक डॉ मनिगोपा चक्रवर्ती ने की है. बेबीकॉर्न की 48 से 65 दिनों वाली इस किस्म तीन तोडाई में प्रति एकड एक से सवा लाख की आमदनी ली जा सकती है. 90 से 95 दिनों की बिरसा मक्का 3 से प्रति एकड साढ क्विंटल उपज व किसान खुद बीज रख सकते है। डॉ चक्रवर्ती ने कहा कि इन दोनों किस्मों से दुगुनी आमदनी को देखते हुए राज्य के कृषक महिलाओं में बेबीकॉर्न की व्यावसायिक खेती लाभप्रद साबित होगी।

समाचार पत्र के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से विवरण

घोषणा

फार्म-4

1. प्रकाशन स्थल	: रांची
2. प्रकाशन अवधि	: साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	: केदार प्रसाद सिंघल
क्या भारत के नागरिक हैं	: हां
पता	: प्लॉट नंबर 535/1272ललगुटवा, पीएस - रातू, रांची, झारखंड
4.प्रकाशक का नाम	: मनोरंजन सिंह
क्या भारत के नागरिक हैं	: हां
पता :	: सरोवर नगर,देवी मंडप रोड,पोस्ट : हेहल, पीएस : सुखदेव नगर, रांची, झारखंड
5.संपादक का नाम	: मनोज कुमार शर्मा
क्या भारत के नागरिक हैं	: हां
पता :	: सरोवर नगर, देवी मंडप रोड,पोस्ट : हेहल, पीएस-सुखदेव नगर, रांची, झारखंड
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	: सन कम्युनिकेशन

मैं मनोरंजन सिंह एतद द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

हस्ताक्षर
मनोरंजन सिंह
(प्रकाशक का हस्ताक्षर)

फोटो न्यूज

ठिक हो गया लकी

इस कुत्ते का नाम लकी है जो मोराबादी स्थित कॉलेज कैंपस में रहता है। सोमवार को किसी ने इस पर बाइक चढा दिया ,यह पिछले पैर से लाचार हो गया थ। ग्रीन रिवोल्ट के संपादक ने इसे ले जाकर सरकारी पशु अस्पताल में इलाज करवाया अब यह ठिक हो रहा है।

सर्वश्रेठ गोपालक बने धोनी

खेती बाड़ी के साथ ही पोल्ट्री और डेयरी में हाथ आजमाने वाले माही को मिला पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ गोपालक का सम्मान

रांची के राजुकमार अपने महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ क्रिकेट के मैदान के ही धुरंधर नहीं हैं बल्कि अब एक सफल कृषक और पशुपालक भी हैं। धोनी के फार्म हाउस में आर्गेनिक तरीके से स्ट्राबेरी और सब्जियों की खेती तो होती ही हैं अब अपने माही भाई ने गो पालन में सफलता प्राप्त कर ली है। है। इसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में धोनी को पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ गोपालक सम्मान से सम्मानित किया गया।

धोनी के पास हैं छह दर्जन से ज्यादा गायें

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब खेल के मैदान की जगह खेती-किसानी के मैदान में रिकॉर्ड कायम कर रहे है। रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक कृषि मेला सह एग्रोटेक किसान मेला में शनिवार को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने एमएस धोनी को पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ गोपालक का सम्मान दिया। धोनी की गैर मौजूदगी में उनके कर्मचारी कुणाल गौरव ने यह सम्मान लिया। एमएस धोनी की ओर से भी इस मेले में अपने फॉर्म हाउस सह डेयरी में रहने वाले कुछ गायों की प्रदर्शनी लगायी गयी थी। धोनी के प्रतिनिधि रूप में सम्मान ग्रहण करने पहुंचे कुणाल गौरव ने बताया कि धोनी इन गायों को बहुत प्यार करते है, वे जब भी रांची स्थित अपने फार्म हाउस आते है, तो दिन में एक बार इनके पास जरूर आते हैं।

कुणाल गौरव ने बताया कि धोनी अभी अपने डेयरी फार्म में 70 से अधिक गायों का पालन कर रहे हैं। इनमें फ्रेजियन

और साहिवाल नस्ल की गाय शामिल है, इन्हें इन्हें पंजाब से लाया गया है। इनसे रोजाना लगभगा 400 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। गायों का सारा दूध काउंटर से ही बेचा जाता है। रांची के लालपुर में ईज फार्म से ही दूध बेचा जाता है। फ्रेजियन नस्ल की गाय का दूध 55 रुपये लीटर और साहिवाल नस्ल की गाय का दूध 85 रुपये लीटर होम डिलीवरी किया जा रहा है।

स्वयं अपने गायों की सेवा भी करते हैं धोनी

गौरव ने बताया कि धोनी गायों की सेवा भी करते हैं। उनके खानपान और उनको दी जाने वाली डोज पर भी खास नजर रखते है। यहां तक की दूध के एक-एक लीटर का भी हिसाब रखते हैं। धोनी के खटाल में 300 गायों को रखने की जगह है। इसके अलावा धोनी गाय के एक बेहतर ब्रीड भी तैयार में लगे हुए हैं। उनके खटाल के सूत्रों की मानें तो वो ये ब्रीड यहां के किसानों को भी उपलब्ध कराएंगे।

धोनी के फॉर्म हाउस की सब्जियों की दुबई में होगी आपूर्ति

दूध के अलावा धोनी ऑर्गेनिक सब्जी की खेती भी कर रहे हैं। धोनी इसे लोकल बाजार के साथ विदेश में भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड सरकार की मदद से दुबई के एक्सपोर्टर से बात भी फाइनल हो गई है। बहुत जल्द इसकी ट्रांसपोर्टिंग भी शुरू हो जाएगी।

सफल और उम्मीदों वाला रहा राज्यस्तरीय किसान मेला

.....पेज एक का शेष

कृषि सूचना, संचार एवं विपणन, कृषि में उच्च शिक्षा , वन संसाधन उपयोग एवं कृषि वानिकी, उद्यान प्रदर्शनी एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन विषयों पर प्रदर्शित तकनीकी को किसानो के लिए लाभकारी बताया. समारोह में विशिष्ट अतिथि संतोष सत्पथी ने भी भाग लिया. संचालन शशि सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ जगरनाथ उराँव ने दी।

मेला के उद्घघाटन समारोह के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मेले परिसर में लगे उद्यान प्रदर्शनी के भव्य पंडाल का भी उद्घघाटन किया. इस प्रदर्शनी में झारखण्ड प्रदेश के बागवानी क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए पंडाल में सब्जी मसाले, फल, गमले में फूल एवं पत्तेदार पौधे, कट फ्लावर, संरक्षित फल - पदार्थ आदि के विभिन्न वर्ग एवं खंड के अधीन प्रादर्श को प्रदर्शित किया गया.

मेला में स्टॉल :मेले में कुल 145 स्टॉल लगे है. मुख्य पंडाल में मुख्य थीम से सबंधित प्रौद्योगिकी प्रदर्शित किया गया है. अन्य पंडालो में ग्यारह सब थीम विषयों पर आधारित स्टॉल में कृषि तकनीकी को प्रदर्शित किया गया है. स्टॉलों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मल्चिंग खेती तकनीक, मृदा स्वास्थ्य, मिट्टी की जाँच एवं जैविक व जीवाणु खाद के बारे में, फसलोत्पादन एवं समन्वित कृषि प्रणाली के तहत एक एकड़ व एक हेक्टेयर हेतु उपयुक्त समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल से आमदनी बढाने तथा फसलों के पार्थेनियम सहित हानिकारक खर-पतवार के बारे में ।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भय, कितना झूठ कितना सच?

किसानों की बड़ी चिंता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (अनुबंध खेती) को लेकर है। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) अहमदाबाद के सेंटर फॉर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर के चेयरमैन एवं प्रोफेसर सुखपाल सिंह कहते हैं कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पिछले 30 वर्षों से हो रही है। पंजाब और हरियाणा के कई किसानों को इसका फायदा भी हुआ। इससे सभी किसानों को फायदा होगा, ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पहली जरूरत होती है बड़ा भू-भाग, कम से कम 5 एकड़ और वह भी पूरी तरीके से सिंचित, जो सभी किसानों के पास नहीं होता। दूसरी बात, यह कि किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच लिखित समझौता होता है। दुःखद पहलू यह है कि सभी किसान पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसलिए किसान गुमराह हो सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ छोटे किसानों को नहीं होगा। अलाभकारी खेती के कारण वे एक न एक दिन अपनी जमीन बेच देंगे। यही किसान की सबसे बड़ी चिंता है।

कारपोरेट्स की योजना

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम कर रहा इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन उद्योगों की व्यवसायिक गतिविधियों पर नजर रखता है। इसके अनुसार,

ई-कॉमर्स कंपनी एमेजन ने फूड रिटेल सेक्टर में अगले पांच साल के दौरान 515 मिलियन डॉलर निवेश की घोषणा की है

पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने अपना सालाना राजस्व 2,800 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है

अमेरिका की फूड कंपनी कारगिल इंक ने 8 लाख रिटेल आउटलेट तक अपनी पहुंच बनाने और अपने तेल ब्रांड सनफ्लावर को देश के तीन प्रमुख ब्रांडों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

नेस्ले इंडिया ने 700 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है

नवंबर 2019 में हल्दीराम ने अमेजन के साथ करार किया है

कोका कोला ने हाल ही में फ्रूट जूस लॉन्च किया है

नवंबर 2020 में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नेचर प्रोटेक्ट नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है

खरपतवार नाशकों से बढ़ रहा है मिट्टी में एंटीबायोटिक प्रतिरोध

एजेंसियां :वैज्ञानिकों ने मिट्टी के जीवाणुओं पर ग्लाइफोसेट, ग्लूफ़ोसिनेट और डाइकाम्बा नामक तीन व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले खरपतवार नाशकों के प्रभाव का अध्ययन किया।

यॉर्क विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन से पता चला है कि खरपतवार नाशकों का उपयोग मिट्टी में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को बढ़ा सकता है। खरपतवार नाशक (हर्बिसाइड्स) खेती में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों में से एक हैं। इनका उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। वे मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक, संभवतः ये सूक्ष्मजीवों के पारिस्थितिक गुणों को बदलते हैं।

चीन और यूके के वैज्ञानिकों ने मिट्टी के जीवाणुओं पर ग्लाइफोसेट, ग्लूफ़ोसिनेट और डाइकाम्बा नामक तीन व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले खरपतवार नाशकों के प्रभाव का अध्ययन किया। मिट्टी के सूक्ष्मजीवों का उपयोग करते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि खरपतवार नाशकों ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन ले जाने वाले बैक्टीरिया प्रजातियों में बहुत अधिक वृद्धि की। ऐसा इसलिए था क्योंकि खरपतवार नाशक की उपस्थिति में वृद्धि को सुधारने वाले उत्परिवर्तन ने एंटीबायोटिक दवाओं के लिए बैक्टीरिया की सहनशीलता भी बढ़ा दी थी। खरपतवार नाशक के संपर्क में आने से बैक्टीरिया के बीच एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन के लगातार अधिक गतिविधि के कारण ऐसा हुआ।

इसी तरह के स्वरूप चीन के 11 कृषि क्षेत्रों में पाए गए जहां खरपतवार नाशक के उपयोग और मिट्टी में इसके अवशेष, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीनों के बढ़े हुए स्तर से जुड़े थे।

जीव विज्ञान विभाग के डॉ. विले फ्रिमन ने कहा हमारे परिणामों से पता चलता है कि खरपतवार नाशकों का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से कृषि की जाने वाली मिट्टी के सूक्ष्मजीवों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास को बढ़ा सकता है, जो बार-बार खरपतवार नियंत्रण के दौरान खरपतवार नाशकों के संपर्क में आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन खरपतवार नाशक की मात्रा अधिक होने पर और अधिक बढ़ रहे थे जो बैक्टीरिया के लिए घातक नहीं थे। इससे पता चलता है कि पहले से ही बहुत कम स्तर के खरपतवार नाशक से मिट्टी की जीवाणु आबादी की आनुवंशिक संरचना में काफी बदलाव आ सकता है। इस तरह के प्रभाव वर्तमान में पारिस्थितिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों में शामिल नहीं हो पाते हैं। जबकि एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन हानिकारक नहीं हैं, वे नैदानिक उपचार के दौरान एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को कम कर देते है। इसलिए प्रतिरोध जीन की आवृत्ति कम रखना एंटीबायोटिक दवाओं की लंबे प्रभाव को बनाए रख सकता है। चूंकि प्रतिरोध जीन वातावरण में आसानी से जा सकते हैं, इसलिए दुनिया भर में कृषि क्षेत्र प्रतिरोध जीन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। यह अध्ययन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवलूशन में प्रकाशित हुआ है।

अध्ययन के निष्कर्ष में कहा गया है कि सूक्ष्मजीवों पर इन खरपतवार नाशकों की मात्रा के प्रभावों का एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन की व्यापकता के लिए जुड़े खतरों को पूरी तरह से समझने के लिए पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

सीसीएल में सेवानिवृत कर्मियों को दी गयी भावभीनी विदाई

संवाददाता :सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों डॉ. मंजू मिश्रा, सीएमएस सीसीएल, मेडिकल विभाग;शिवा राम बनर्जी, महाप्रबंधक स-रक्षा विभाग; अनिल कुमार साव, विभागाध्यक्ष/मुख्य प्रबंधक आईएडी विभाग; भरत भुषण श्रीवास्तव, अकाउंटेंट-'ए-1', वित्त-ईपीआर विभाग; मो. सलिम खान, ड्राईवर, कैट श्क सामान्य प्रशासन विभाग को सीसीएल परिवार की ओर से सीसीएल मुख्यालय में ''सम्मान समारोह''का आयोजन कर भावभीनी विदाईदी गई।

अवसर विशेष पर सीसीएल द्वारा निर्मित सेवानिवृत कर्मियों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन 'सम्मान समारोह'के दौरान किया गया। फिल्म के माध्यम से सेवानिवृत कर्मियों ने अपने-अपने कार्यानुभवों एवं विचारों को व्यक्त किया। फिल्म में सेवानिवृत कर्मियों ने कंपनी के दिन दूनी रात चौगुनी सफलता की कामना की। सभी कर्मियों ने कहा कि कंपनी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पूरा करने तत्पर रहेगा और देश की उर्जा की आवश्यकता को पूरा करने में कंपनी अहम भूमिका निभायेगा। सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने सेवानिवृत कर्मियों को संबोधित करते हुये कहा कि

सीसीएल मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रों में सेवानिवृत कर्मियों कंपनी के लिए अहम योगदान दिये हैं जिसके कारण कंपनी निरंतर कोयला उत्पादन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव ने कहा कि उनके आगे की जीवन के लिए शुभकामनाएं दी तथा उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना की। निदेशक (वित्त) एन.के. अग्रवाल ने कहा कि सीसीएल सेवानिवृत हो रहे सदस्यों के सुझाव को मानकर आगे बढ़ते रहेंगे। सीवीओ एस.के. सिन्हा ने कहा कि सभी सेवानिवृत कर्मियों कंपनी में अपना बहुमूल्य योगदान दिये हैं जिसके कारण कंपनी निरंतर अच्छा कर रहा है। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। निदेशक (कार्मिक), ईसीएल विनय रंजन जो सीसीएल के अतिरिक्त प्रभार में हैं ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट किये और सभी को पोस्ट रिटायरमेंट लाईफ एवं एक्टीव रहने की कामना किये। महाप्रबंधक(कल्याण) डॉ. ए.के. सिंह ने समारोह के मुख्य आकर्षण सेवानिवृत कर्मियों को कंपनी की ओर से स्वागत किया। साथ ही सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उन्हें सेवानिवृत बेनिफिट प्रदान किया गया। इस अवसर पर सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर के चिकित्सकगण एवं सेवानिवृत कर्मियों के परिवारजन सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे।कार्यक्रम का संचालन डॉ. ए.के. सिंह ने किया।

सीएमपीडीआई परिवार के 3 सदस्यों को दी गयी विदाई

28 फरवरी, 2021 को सेवानिवृत्त हुए सीएमपीडीआई परिवार के 3 सदस्यों को आज संस्थान के ''कांफ्रेंस हॉल'' में आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इनमें श्री प्रभु प्रसाद- पूर्व महाप्रबंधक (भूविज्ञान), डी0के0 शाह-पूर्व मुख्य प्रबंधक (पर्यावरण) एवं श्री सुनील कुमार मिश्रा-पूर्व मुख्य प्रबंधक (उत्खनन) शामिल हैं।

इस मौके पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने सेवानिवृत्त कर्मियों को पुष्पगुच्छ, मान-पत्र, प्रतीक चिह्न व शॉल देकर कम्पनी की ओर सम्मानित किया।इस अवसर पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन एवंनिदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0 के0 गोमास्ता ने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। श्रमिक प्रतिनिधि के0बी0 शिरोमणि एवं महाप्रबंधक (पर्यावरण/खनन) अभिजीत सिन्हा ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन तथा धन्यवाद ज्ञापन वरीय प्रबंधक (कार्मिक) नवीन कुमार सिन्हा ने किया।

भारत में हर वर्ष करीब 6.88 करोड़ टन भोजन कर दिया जाता है बर्बाद

देश में हर व्यक्ति प्रतिवर्ष करीब 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है, जबकि 18.9 करोड़ लोगों को आज भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है

भारत में हर वर्ष करीब 6.88 करोड़ टन भोजन बर्बाद कर दिया जाता है। यदि इसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष 50 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट 'फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021' में सामने आई है। वहीं विडम्बना देखिए की देश में अभी भी करीब 14 फीसदी आबादी कुपोषण का शिकार है, जिसका मतलब है कि 18.9 करोड़ लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। आज भी 5 वर्ष से कम आयु के 34.7 फीसदी बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से काफी छोटे हैं, जिसका मतलब है कि पोषण की कमी के चलते उनका उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। वहीं यदि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को देखें तो उसके अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को 94वें स्थान पर रखा गया है जो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि देश में अभी भी सबको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पता है।

यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो 2019 में करीब 93.1 करोड़ टन भोजन बर्बाद कर दिया गया था, जबकि उस वर्ष में 69 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा था। इसके वजन का अनुमान आप इसी बात

से लगा सकते हैं कि यदि इस कचरे को यदि 40 टन के ट्रकों में पूरी तरह भर दिया जाए तो यह यह इस तरह के 2.3 करोड़ ट्रकों के वजन के बराबर होगा। जिन्हें लाइन में खड़ा करने पर पृथ्वी का सात बार चक्कर लगाया जा सकता है। अनुमान है कि 17 फीसदी भोजन को हर वर्ष कचरे में फेंक दिया जाता है, जिससे करोड़ों लोगों की भूख मिटाई जा सकती है। इसमें से 57 करोड़ टन अकेले घरों द्वारा कचरे में फेंका गया भोजन होता है।

कौन सा देश कितना करता है फूड वेस्ट? इस रिपोर्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई की एक तरफ तो अफ्रीका के कई देश भुखमरी का सामना कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ ना-इजीरिया जैसे देश भी हैं जहां हर व्यक्ति साल में करीब 189 किलोग्राम भोजन बर्बाद कर देता है। इसी तरह रवांडा में हर व्यक्ति द्वारा 164 किलोग्राम भोजन को कचरे में फेंक दिया जाता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका जैसा देश भी है जिसमें प्रति व्यक्ति 40 किलोग्राम भोजन को कचरे में फेंक देता है, जोकि वैश्विक औसत (74 किलोग्राम प्रति व्यक्ति/ प्रति वर्ष) से काफी कम है। इस लिहाज से देखें तो रूस में सबसे कम भोजन बर्बाद किया जाता है, वहां प्रति व्यक्ति करीब 33 किलोग्राम भोजन को हर वर्ष कचरे में फेंका जाता है।

पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी यह बहुत मायने रखता है, एक तरफ तो इस भोजन को पैदा करने में जो संसाधन खर्च होते हैं वो पूरी तरह बर्बाद चले जाते हैं। दूसरी तरह इससे प्रदूषण और कचरे में इजाफा होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार यदि भोजन के नुकसान और बर्बादी को यदि एक देश मान लिया जाए तो यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में तीसरे स्थान पर होगा। जो भोजन बेकार चला जाता है, वो वैश्विक उत्सर्जन के करीब 8 से 10 फीसदी हिस्से के लिए जिम्मेवार होता है।

बर्बादी को रोकने से बचाए जा सकते हैं 68.4 लाख करोड़ रुपए

यदि इस बर्बादी को रोक दिया जाए तो न केवल करोड़ों लोगों को भोजन मिल पाएगा, साथ ही इसके चलते हर वर्ष होने वाले करीब 68,39,675 करोड़ रुपए (94,000 करोड़ डॉलर) के आर्थिक नुकसान को टाला जा सकता है, जोकि किसानों और लोगों की भलाई के लिए खर्च किया जा सकता है।

आज खाना बर्बाद करना हमारी एक आदत बनता जा रहा है। शादी और पार्टी में यदि खाना अच्छा न हो तो दावत पूरी नहीं होती। पर दावत के बाद न जाने कितनी प्लेटों में वो शानदार खाना बचा रहता है क्या कभी आपने उसका अनुमान लगाया है। क्या कभी सोचा है जो खाना आप और हम बर्बाद कर रहें है उससे किसी और का पेट भी भर सकता है।

इस बर्बादी को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसके लिए हमें अपनी आदत बदलनी होगी। अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना हम खा सकते हैं। उतना ही खरीदें जितना हमारे लिए पर्याप्त है। बेवजह खाद्य पदार्थों को जमा करना बंद कर दें। भोजन के महत्त्व को समझें। यह इंसान के लिए सबसे जरुरी चीजों में से एक है। अगली बार जब भी अपनी थाली में खाना बाकी छोड़ें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं इसी खाने की वजह से कोई भूखा सोने को मजबूर है

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।